>

Title: Need to implement the recommendations of Renke Commission for the welfare of nomadic and semi-nomadic tribes in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस देश के लगभग 15 करोड़ लोगों के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। इस सदन में आजादी के 62 साल बाद भी गरीबी मिटाने, बेरोजगारी दूर करने, सबको शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुहैया कराने की बात की जाती है, लेकिन आजादी के इन 62 वर्षों बाद भी कोई इस देश में राम राज्य लाना चाहता है, कोई समाजवाद लाना चाहता है, कोई अम्बेडकरवाद लाना चाहता है, तो कोई गांधीवाद लाना चाहता है। मगर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके बारे में न तो गांधीवाद के लोगों ने आज तक सोचा, न राम राज्य वालों ने सोचा, न अम्बेडकरवाद वालों ने सोचा और न ही समाजवादी लोगों ने सोचने का काम किया है। आज 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हालत जानवरों से भी बदतर है। उनके पास न रहने के लिए मकान है और न ही शिक्षा का कोई इंतजाम है, यहां तक कि उनको राशन कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परिपेक्ष्य में एक नैशनल ओबीसी कमीशन की कांफ्रेंस हुई थी। आज 62 साल की आजादी के बाद भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो घुमन्तु टाइप के हैं, जो जंगलों, सड़कों और नदी-नालों के किनारे अपना जीवनयापन कर रहे हैं। जब भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, तब 15 करोड़ लोगों के बारे में अगर सदन में बैठकर गंभीरता से चर्चा न की जाये, तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा संवेदनहीन मामला कोई और नहीं हो सकता।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जब इस देश में बंगाल से आने वाले लोगों के निवास की व्यवस्था की गयी, उनकी रोटी-रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, तो इन 15 करोड़ लोगों के बारे में जो अपने को भारतीय मानते हैं, जो अपने को हिन्दू कहते हैं, जो लोग अपनी ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर क्रिश्चियन धर्म अपना सकते थे, वे अपना धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन वे आज भी भारतीय बने हुए हैं, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किया है। मंडल कमीशन ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। एलेन नाइक ने कहा था कि इन लोगों की हालत एससी और एसटी लोगों से भी बदतर है, इनके लिए अलग से कोई प्रावधान करके, इन्हें देश की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाए।

महोदया, आज इन 15 करोड़ लोगों के प्रतिनिधिमंडल जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके संरक्षण में यह मांग करता हूं कि सहमति बनाकर, जिस प्रकार से एससी-एसटी लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इन घुमन्तू लोगों के बारे में भी की जाए। हम जानते हैं कि यूपीए सरकार की चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये 15 करोड़ लोग वे हैं, जो देश की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। उन्हें इस देश की मुख्यधारा में लाने के लिए आप हस्तक्षेप करके इन 15 करोड़ लोगों को संविधान में प्रावधान करके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार को निर्देश दें। मैं ऐसी मांग करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।